इंडिया सेमेन्ट्स लिमिटेड। , मद्रास

बनाम

आयकर आयुक्त, मद्रास

8 दिसंबर, 1965

[के. सुब्बा राव, जे. सी. शाह और एस. एम. सिकरी, जे. जे.]

1 भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922,धारा 10 (2) (xv)- कम्पनी द्वारा ऋण- प्राप्त किया गया- ऋण प्राप्त करने के लिये खर्च किये गये स्टाम्प शुल्क एवं अन्य व्यय-क्या पूंजी या राजस्व व्यय-व्यवसाय के उद्देश्य के लिए निर्धारित किए गए या नही।

2 मूल्यांकन वर्ष 1950-51 के लिए प्रासंगिक लेखांकन अवधि के दौरान अपीलकर्ता कंपनी ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से 40 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया। कंपनी की अचल संपत्तियों पर शुल्क लगाकर ऋण सुरक्षित किया गया था। रुपये 84,633 की राशि उक्त लेखा वर्ष के लिए बैलेंस शीट में बंधक ऋण व्यय के रूप में दिखाए गइ थी; राशि को लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में चार्ज नहीं किया गया था। 31 मार्च 1953 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के खातों में, यह राशि उस वर्ष के मुनाफे के विरुद्ध विनियोजन द्वारा लिखी गई थी। आयकर अधिकारी ने कटौती की अनुमति नहीं दी; उन्होने पाया कि उक्त व्यय पूंजी प्राप्त करने में किया गया था और इसे उधार ली गई पूंजी पर ब्याज से अलग किया

जाना चाहिए, जो अकेले धारा 10(2)(iii) के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य था। उनके विचार में उपरोक्त व्यय पूंजीगत प्रकृति का था और इसलिए 10(2)(xv) धारा के तहत स्वीकार्य नहीं था। मध्यवर्ती कार्यवाही के बाद उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में आयकर अधिकारी के दृष्टिकोण को बरकरार रखते का निष्कर्ष दिया। अपीलकर्ता विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय में आया था।

3 अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि:

(1) विचाराधीन व्यय किसी संपत्ति या चिरस्थायी-प्रकृति का लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया था;

(2) इसे पूर्णतः और विशेष रूप से व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए लागू किया गया था; और

(3) धारा 10(2)(xv) के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य था।

4 निष्कर्ष: मामले की परिस्थितियों को देखते हुए विचाराधीन व्यय धारा 10(2)(xv) के तहत राजस्व व्यय था।

5 (i) जब कोई स्पष्ट निषेध नहीं है, तो एक जावक, जिसके माध्यम से एक निर्धारिती उस चीज़ का उपयोग करता है जिससे वह लाभ कमाता है, तो वह बहिर्गमन कर योग्य आय सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय की प्राप्तियों से कटौती योग्य है। हस्तगत मामले मे, ऋण द्वारा प्राप्त धन वह वस्तु थी जिसके उपयोग के लिए यह व्यय किया गया था।

सिद्धांतिक रूप से, किसी भी वैधानिक प्रावधान के होते हुए, ऋण के संबंध में ब्याज और ऋण प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय के बीच कोई अंतर नहीं है जैसा कि आयकर अधिकारी द्वारा बताया गया [950 जी-एच]

6 (ii) प्राप्त ऋण को निर्धारिती के व्यवसाय के स्थायी लाभ के लिए संपत्ति या लाभ के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऋण एक दायित्व है और उसे चुकाना पड़ता है और दायित्व को परिसंपत्ति या लाभ मानना गलत है। (955 सी)

7 (iii) ऋण जुटाने में होने वाले व्यय की प्रकृति को ऋण की प्रकृति और उद्देश्य पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। जब किसी ऋण पर बातचीत की जाती है तो उसका उपयोग कच्चे माल की खरीद के लिए किया जा सकता है, लेकिन कंपनी ऋण लेने के बाद अपना मन बदल सकती है और इसे पूंजीगत संपत्ति सुरक्षित करने पर खर्च कर सकती है। [955-II-956 बी]

8 (iv) कंपनी के व्यवसाय को चलाने की सुविधा के लिए ऋण स्वेच्छा से दिया गया था और यह नहीं कहा जा सकता है कि यह पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं दिया गया था।[958 बी)

9 न्यायिक दृष्टांक जिन पर विचार किया गया.

10 सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1106/1964

11 1958 के कर मामले संख्या 67 में मद्रास उच्च न्यायालय के 31 अक्टूबर, 1961 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील

12 अपीलकर्ता की ओर से ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री, आर. वेंकटरमन और आर. गोपालकृष्णन।

13 प्रत्यर्थी की ओर से एस.टी.देसाई, गोपाल सिंह, बी.आर.जी.के. आचार और आर.एन.सचथे।

14 न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

15 सीकरी, जे.

वह विशेष अनुमति द्वारा यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें प्रतिवादी के पक्ष में कानून के निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दिया गया है:

> 16 "क्या मामले की तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल यह मानने में सही था कि करदाता द्वारा ऋण या उसके किसी हिस्से को प्राप्त करने में खर्च की गई 84,633/- रुपये की राशि स्वीकार्य व्यय है?"

17 मामले के बयान में ट्रिब्यूनल द्वारा बताए गए मामले के तथ्य और परिस्थितियां इस प्रकार हैं: अपीलकर्ता- इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, मद्रास, जिसे इसके बाद निर्धारिती के रूप में संबोधित किया जायेगा, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। प्रश्न निर्धारण वर्ष 1950-51, लेखांकन अवधि 1 अप्रैल 1949 से 31 मार्च 1950 के संबंध में उठता है। लेखांकन वर्ष के दौरान कम्पनी ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से 40 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया। यह ऋण कंपनी की अचल संपत्तियों पर चार्ज द्वारा सुरक्षित किया गया था। चूंकि प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री एस. टी. देसाई ने अपीलकर्ता न्यायाधिकरण द्वारा बताए गए कुछ तथ्यों पर विवाद किया है, इसलिए इन तथ्यों को अपीलीय न्यायाधिकरण के शब्दों में देना सुविधाजनक होगा। मामले के बयान में कहा गया है कि

> "इस ऋण की आय का उपयोग मेसर्स ए.एफ. हार्वे लिमिटेड और मदुरै मिल्स लिमिटेड के 25 लाख के पूर्व ऋण का भुगतान करने के लिए किया गया था। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि 15 लाख का शेष ऋण निदेशको द्रारा खातो की समाप्त वर्ष 31-03-1949 के लिए खातों पर रिपोर्ट करते समय किस प्रकार इस्तेमाल किया गया था लेकिन समाप्त वर्ष 31-03-1949 के खातो को रिपोर्ट करते समय 4-10-1949 में कहा गया कि इसका उपयोग कार्यशील निधि के लिए किया गया था।"

इस ऋण के संबंध में 84,633/- रुपये का व्यय निम्नलिखित मदों से बना था:

18 टिकटों	60,023.00
पंजीकरण शुल्क	16,067.00
बंधक विलेख की प्रमाणित प्रति के लिए शुल्क	28.00
एस्सेन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा क्षतिपूर्ति विलेख	15.00
विलेख का मसौदा तैयार करने के लिए वकील का शुल्क	7,500.00
कानूनी फीस	1,000.00
कुल रु.	84,633. 0 0

19 निर्धारिती ने इस व्यय को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में चार्ज नहीं किया। इसे बैलेंस शीट में बंधक ऋण व्यय के रूप में दिखाया गया था। 31 मार्च, 1952 तक ऐसा ही दिखाया जाता रहा। 31 मार्च, 1953 के खातों में इसे उस वर्ष के मुनाफे के विरुद्ध विनियोग द्वारा बट्टे खाते में डाल दिया गया था।

20 आयकर अधिकारी ने रुपये 84,633/- की कटौती की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने पाया:

"लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ऋण के 25 लाख रुपये मेसर्स ए.ई.एफ. हार्वे, लिमिटेड और मथुराई मिल्स, लिमिटेड को भुगतान किए जाने थे, उनसे उधार ली गई राशि का भुगतान किया जाना था और इसका उपयोग कंपनी की पूंजीगत संपत्ति पर किया जाना था। हालाँकि कंपनी के बही-खातों में रु. 84,633 को राजस्व में नहीं लिया गया था, लेकिन आयकर के प्रयोजनों के लिए इसे पूंजीकृत किया गया और बैलेंस शीट में आगे बढ़ाया गया, कंपनी के लेखा परीक्षक इसे राजस्व व्यय की स्वीकार्य वस्तु के रूप में दावा करते हैं। "

21 उनका मानना था कि व्यय पूंजी प्राप्त करने में किया गया था और इसे उधार ली गई पूंजी पर ब्याज से अलग किया जाना चाहिए जो कि धारा 10(2)(iii) के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य था। उनके अनुसार, एस. 10(2)(xi) विशेष रूप से पूंजीगत व्यय की किसी भी मद को विचार से बाहर रखता है। उन्होंने आगे कहा कि यह मामला द नागपुर इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी बनाम आयकर आयुक्त, मध्य प्रांत (6 आई.टी.सी. 28) के फैसले से अलग नहीं है। अपीलीय सहायक आयुक्त आयकर अधिकारी से सहमत हुए। अपीलीय न्यायाधिकरण ने नागपुर इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी बनाम आयकर आयुक्त(6 आई.टी.सी. 28)

इस आधार पर पृथक किया कि नागपुर इलेक्ट्रिक लाइट के मामले में पूंजी प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च किया गया था। उन्होने पाया की:

> 22 "यहां हम स्थिति को अलग पाते हैं। कंपनी की 31-3-1949 की बैलेंस-शीट के अध्ययन से इस तथ्य का पता चलता है कि भुगतान की गई पूंजी कंपनी के संपूर्ण पूंजी परिव्यय को कवर करने के लिए पर्याप्त थी और 25 लाख रुपये की अतिरिक्त उधारी कंपनी की कामकाजी निधि को बढ़ाने के लिए थी। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उस प्रारंभिक चरण में भी पैसा उधार लिया गया था और इसका उपयोग पूंजीगत उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि कंपनी की कामकाजी निधि को बढ़ाने के लिए किया गया था। इसलिए, हम मानते हैं कि संपूर्ण बंधक ऋण का उपयोग सबसे पहले 25 लाख रुपये के ऋण का भुगतान करने और शेष राशि कामकाजी निधि के लिए और इस तरह, पूरी राशि पूरी तरह से कामकाज बढ़ाने के उद्देश्यों के लिए थी। यह नहीं कहा जा सकता कि इसका उपयोग पूंजीगत उद्देश्यों के लिए किया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण से, हम मानते हैं कि ऋण प्राप्त करने में खर्च किया गया धन एक स्वीकार्य व्यय है।"

23 उच्च न्यायालय ने आयकर अधिकारी और न्यायाधिकरण के निष्कर्षों पर गौर करने के बाद आयकर अधिकारी द्वारा दिए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों को प्राथमिकता दी। यह पायाः

> "इस स्तर पर, हम यह बता सकते हैं कि ट्रिब्यूनल द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि पैसा केवल कामकाजी खर्चों के लिए उधार लिया गया था, न कि पूंजी निवेश के लिए, बैलेंस शीट के आधार पर एक अनुमान पर आगे बढ़ा। ट्रिब्यूनल ने जांच नहीं की ए. एच. हार्वे और मदुरै मिल्स लिमिटेड से पहले उधार ली गई 25 लाख रुपये की राशि का वास्तव में उपयोग कैसे किया गया। हालांकि आयकर अधिकारी के आदेश में यह पाया गया है कि उस राशि का उपयोग कंपनी की पूंजीगत संपत्ति पर किया गया था और वह बयान करदाता के लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई जानकारी के अधिकार पर आधारित था, ट्रिब्यूनल ने या तो इस परिस्थिति को नजरअंदाज कर दिया या अनदेखा कर दिया। आयकर अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान के सामने, ट्रिब्यूनल द्रारा अनुमान के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुचना की क्या पहले का उधार पूंजी या राजस्व खाते पर था न्यायोचित नही था।"

24 विभिन्न मामलों की समीक्षा के बाद उच्च न्यायालय ने कहा, "अगर हम पूछें कि वर्तमान मामले मे खर्च किस उद्देश्य के लिए किया गया एकमात्र उत्तर यह होना चाहिए कि यह 40 लाख रुपये लेने के रूप में एक संपत्ति को अस्तित्व में लाने के उद्देश्य से खर्च किया गया था।. अगला प्रश्न यह होगा कि क्या यह संपत्ति या लाभ व्यवसाय के स्थायी लाभ के लिए नहीं था और क्या किया गया व्यय वह था जो एक बार और हमेशा के लिए किया गया था। दोनों प्रश्नों का उत्तर फिर से सकारात्मक होगा। यह सच है कि उधार लिया गया पैसा चुकाना पड़ता है और यह एक स्थायी लाभ नहीं हो सकता है, इस अर्थ में कि पैसा आने वाले समय के लिए कंपनी की संपत्ति का हिस्सा बन जाता है। लेकिन, यह निश्चित रूप से एक लाभ है जो कंपनी को ऋण की अवधि से प्राप्त होता है और निस्संदेह यह व्यवसाय के लाभ के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं हो सकता है जिसके लिए उधार लिया गया था। यह इस अर्थ में टिकाऊ नहीं है कि उधार को छोटी या लंबी अवधि के बाद चुकाना पड़ता है, जैसा कि यह था, इस निष्कर्ष को प्रभावित नहीं कर सकता कि यह फिर भी एक संपत्ति या लाभ था जिसे सुरक्षित किया गया था। उपरोक्त निर्णय असम बंगाल सीमेंट

कंपनी लिमिटेड, बनाम आयकर आयुक्त (27 आई.टी.आर. 34) में दिए गए परीक्षणों के आलोक में देखने पर हमें ऐसा लगता है कि व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाना चाहिए। जैसा कि मामले के तथ्य जो हमने पहले बताए हैं, इंगित करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कम से कम 25 लाख रुपये की सीमा तक की राशि पूंजीगत प्रकृति के प्रयोजनों के लिए खर्च की गई थी, स्पष्ट रूप से पूंजीगत परिसंपत्तियों को अस्तित्व में लाने के लिए। हमने यह भी बताया है कि यद्यपि ट्रिब्यूनल द्वारा यह अस्पष्ट रूप से कहा गया था कि रुपये 15 लाख राशि रुपये का उपयोग कार्यशील निधि के रूप में किया गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचने का औचित्य साबित करने के लिए कोई भी सामग्री नहीं है।"

25 निर्धारिती कंपनी के विद्वान वकील श्री ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री का आग्रह है कि व्यय अधिनियम की धारा 10(2)(xv) के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य है। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि व्यय विस्काउंट केव द्वारा निर्धारित और असम बंगाल सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (27 आई.टी.आर. 34) में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित परीक्षण के भीतर स्थायी प्रकृति की किसी संपत्ति या लाभ को प्राप्त करने के लिए किया गया था। ।

26 वह आगे कहते है कि व्यय द्वारा जो सुरक्षित किया गया था वह एक ऋण था और भारत में ऋण जुटाने में खर्च किया गया धन, चाहे डिबेंचर या बंधक के माध्यम से और चाहे आप इसे ऋण पूंजी कहें या नहीं, प्रकृति में पूंजीगत व्यय नहीं है उन्होंने आगे कहा कि व्यय पूरी तरह से और विशेष रूप से कंपनी के व्यवसाय के उद्देश्य से खर्च किया गया था।"

27 राजस्व के विद्वान वकील, श्री एस.टी.देसाई, उच्च न्यायालय के तर्क का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय इस आधार पर आयकर अधिकारी के निष्कर्षों को प्राथमिकता देने में सही था कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किए गए निष्कर्ष के लिए कोई सामग्री नहीं थी और निष्कर्ष अनुमानों पर आधारित था और भौतिक साक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया गया था। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय एक निर्देश में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किए गए किसी भी तथ्यात्मक निष्कर्ष को नजरअंदाज करने का हकदार है यदि वे निष्कर्ष विकृत हैं। वैकल्पिक रूप से, उनका कहना है कि संदर्भित प्रश्न इतना व्यापक है कि इसमें यह प्रश्न भी शामिल है कि क्या अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्ष के लिए कोई सामग्री थी। गुण-दोष के आधार पर उनका तर्क है कि व्यय उस चीज़ पर निर्भर करता है जिस पर व्यय किया गया है। यदि धन पूंजी प्राप्त करने के लिए खर्च किया जाता है तो व्यय पूंजी व्यय की प्रकृति धारण कर लेता है, लेकिन यदि धन कच्चा माल प्राप्त करने के लिए खर्च

किया जाता है तो व्यय राजस्व व्यय का रंग ले लेता है। वह आगे कहते हैं कि उधार लिया गया धन एक स्थायी संपत्ति है और इस धन को प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी व्यय डिस्काउंट केस द्वारा निर्धारित और इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित परीक्षण के अंतर्गत आता है।

28 मामले की सुनवाई के दौरान दोनों वकीलों द्वारा कई मामलों का उल्लेख किया गया है, लेकिन हम उन सभी के लिए को संदर्भित करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। हमें पहले इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों से शुरुआत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय की प्रकृति के व्यय से अलग करने के लिए क्या सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, और विशेष रूप से उन मामलों में जो समान समस्याओं से निपटते हैं। हम सबसे पहले मद्रास राज्य बनाम जी.जे. सेओल्हो (1964)8 एस.सी..आर. 60: 53 आई.टी.आर. 186) पर विचार करेंगे। यह भारतीय आयकर अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाला मामला नहीं था, बल्कि मद्रास प्लांटेशन्स कृषि आयकर अधिनियम, 1955 के तहत उत्पन्न हुआ था, जिसमें एक धारा बिल्कुल एस के समान थी। 10(2)(xv) अस्तित्व में था। संक्षेप में, उस मामले में तथ्य यह थे कि निर्धारिती ने बागानों को खरीदने के उद्देश्य से धन उधार लिया था और उसने दावा किया था कि इन बागानों से उसकी कृषि आय की गणना करने में उसके द्वारा बागानों को खरीदने के उद्देश्य से उधार लिए गए धन पर

पूरा ब्याज चुकाया गया था को अधिनियम की धारा 5(ई). के तहत वृक्षारोपण को व्यय के रूप में काटा जाना चाहिए।

29 मद्रास अधिनियम में अधिनियम की धारा 10(2)(iii) के समान कोई प्रावधान नहीं था और इस प्रकार ब्याज भत्ते के रूप में स्पष्ट रूप से कटौती योग्य नहीं था। इस न्यायालय ने एथरटन बनाम ब्रिटिश इंसुलेटेड और हेलस्बी केबल्स लिमिटेड(10 टी.सी. 155) में विस्काउंट केव, एल.सी. द्वारा तैयार किए गए परीक्षण को लागू किया जिसे असम बंगाल सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त ((1955) 1 एस.सी..आर.972:22 आई.टी.आर. 34) में न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था, और माना कि ब्याज का भुगतान एक राजस्व व्यय था। यह पाया गया कि

> "इसके साथ कोई नई संपत्ति अर्जित नहीं की जाती है; कोई स्थायी लाभ प्राप्त नहीं होता है। किया गया व्यय निर्धारिती की प्रसारित या अस्थायी पूंजी का हिस्सा था। सामान्य वाणिज्यिक व्यवहार में ब्याज के भुगतान को पूंजीगत व्यय नहीं कहा जाएगा।"

इस न्यायालय ने आगे कहा कि व्यय व्यवसाय के उद्देश्य से था। श्री देसाई ने उस मामले को इस आधार पर अलग करने की कोशिश की कि मुद्दा ऋण पर ब्याज का था न कि ऋण प्राप्त करने के लिए किया गया

व्यय। हमारी राय में भारत में यह भेद करने का कोई औचित्य नहीं है। जैसा कि स्कॉटिश नॉर्थ अमेरिकन ट्रस्ट बनाम फार्मर(5 टी.सी. 693 at 707) में लॉर्ड एटकिंसन ने कहा था,

> "ब्याज, वास्तव में, उनके व्यापार के एक उपकरण के उपयोग या किराये के लिए भुगतान किया गया पैसा है, जितना कि उनके कार्यालय के लिए भुगतान किया गया किराया या एक टाइपराइटिंग मशीन के किराये के लिए किया गया भुगतान है। यह एक आउटगोइंग है जिसके माध्यम से कंपनी उस चीज़ का उपयोग करती है जिसके द्वारा वह लाभ कमाती है, और किसी भी समान आउटगोइंग की तरह प्राप्तियो मे से कटौती की जानी चाहिए जिस से कर योग्य लाभ और लाभ का पता लगाया जा सके जो की कम्पनी कमाती है। अन्यथा, उन पर कल्पित लाभ पर कर लगाया जा सकता था, जबकि वास्तव में, उन्हे घाटा हुआ।"

30 याद रखना चाहिए कि अंग्रेजी आयकर अधिनियम में अधिनियम की धारा 10(2)(iii) जैसी कोई धारा नहीं थी। दूसरी ओर, कुछ नियम थे जो "इस तरह के व्यापार में पूंजी के रूप में निकाली गई किसी भी पूंजी, या नियोजित या नियोजित की जाने वाली किसी भी राशि" के

संबंध में कटौती पर रोक लगाते थे। यदि उपर्युक्त राशि पर कोई ब्याज बनाया गया हो उसे ब्याज से बाहर रखा गया है।

> " लॉर्ड एटकिंसन ने सबसे पहले उस मामले में माना कि व्यक्त निषेध उस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते और फिर सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़े। इन टिप्पणियों से पता चलता है कि जहां कोई व्यक्त निषेध नहीं है, एक आउटगोइंग, जिसके माध्यम से एक निर्धारिती उस चीज़ का उपयोग करता है जिससे वह लाभ कमाता है, कर योग्य आय का पता लगाने के लिए व्यवसाय की प्राप्तियों से कटौती योग्य है। इस मामले के तथ्यों पर, ऋण द्वारा सुरक्षित धन वह वस्तु थी जिसके उपयोग के लिए यह व्यय किया गया था। सिद्धांतिक रूप से, किसी भी वैधानिक प्रावधान के अलावा, हम ऋण के सम्बंध मे ब्याज तथा ऋण प्राप्त करने मे उठाये गये व्यय मे कोई अंतर नहीं देखते हैं-

31 श्री देसाई का आग्रह है कि लॉर्ड एटकिंसन की ये टिप्पणियाँ उस मामले तक सीमित होनी चाहिए जहां अस्थायी उधार लिया जाता है। यह सच है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक कंपनी के मामले से निपट रहा था और जो पैसा उधार लिया गया था वह अस्थायी प्रकृति का था। लेकिन इस

तथ्य पर केवल यह मानने के लिए भरोसा किया गया था कि आयकर अधिनियम, 1842, बी के पहले मामले, धारा 100 (5 और 6 वि. अध्याय 35) के नियम 3 के तहत सुरक्षित धन 'पूंजी' नहीं था। लॉर्ड एटकिंसन ने पृष्ठ 706 पर उल्लेख किया;

> 32 ".... मुझे ऐसा प्रतीत होता है, बस, इसका तात्पर्य यह है कि इस नियम में "पूंजी" शब्द को पूरी तरह से कृत्रिम अर्थ में रखा जाना चाहिए, जो सामान्य अर्थ से पूरी तरह से भिन्न है, हालांकि खंड मे एसा कोई संदर्भ नहीं है कि इसे सामान्य वाणिज्यिक लेनदेन में जो अर्थ दिया जाता है उससे अलग एक अर्थ दिया जाना चाहिए।"

33 फिर उन्होंने यह दिखाने के लिए ब्रायन बनाम मेट्रोपॉलिटन सैलून ओम्निबस कंपनी (3 D.G. and J 123) के फैसले का हवाला दिया कि एक संयुक्त स्टॉक कंपनी द्वारा डिबेंचर जारी करके पैसे उधार लेना कंपनी की पूंजी में वृद्धि के बराबर नहीं है।

34 बॉम्बे स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त ((1965) एस.सी..आर.770:56 .T.R 52) में, इस न्यायालय ने फिर से पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के बीच अंतर करने के सवाल की जांच की।

35 इस न्यायालय ने सबसे पहले मामले के तथ्यों के आधार पर यह माना कि, धारा 10(2) उप धारा (iii) लागू नहीं होता, क्योंकि उस मामले में निर्धारिती क्रेता द्वारा देय प्रतिफल की शेष राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था और इससे, वास्तव में, ऋण को जन्म नहीं देता है। शाह, जे. ने पाया की:

> 36 "क्या कोई विशेष व्यय व्यवसाय के उद्देश्य से किया गया राजस्व व्यय है, इसका निर्धारण सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करके और वाणिज्यिक व्यापार के सिद्धांतों के अनुप्रयोग द्वारा किया जाना चाहिए। प्रश्न को व्यवसाय की आवश्यकता या समीचीनता के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यदि बहिर्गमन या व्यय व्यवसाय को चलाने या संचालन से इतना संबंधित है, कि इसे लाभ कमाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जा सकता है, न कि किसी संपत्ति या संपत्ति के अधिग्रहण के लिए या एक स्थायी चरित्र के अधिकार के लिये, जिसका कब्ज़ा व्यवसाय को चलाने की एक शर्त है, व्यय को राजस्व व्यय माना जा सकता है।"

37 अब हम संक्षेप में उच्च न्यायालयों के प्रासंगिक निर्णयों पर चर्चा करेंगे। संदर्भित पहला मामला टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड

(आई.टी.सी. 125) का है। उस मामले में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ने 28 लाख रुपये का भुगतान कमीशन के रूप मे ग्रहाको को 7 लाख तरजीही शेयरों के इश्यू जो 100 रूपये मुल्य का प्रत्येक था पर किया गया अैार कम्पनी ने भारतीय आयकर अधिनियम (1918 का VII) की धारा 9(2)(ix) तहत खर्च के रूप में इस राशि को काटने का दावा किया। । मैकलियोड, सी.जे., ने देखा:

> 38 "यदि यह स्वीकार किया जाता है कि मूल पूंजी जुटाने की लागत को पहले वर्ष के बाद लाभ से नहीं काटा जा सकता है, तो यह देखना मुश्किल है कि अतिरिक्त पूंजी जुटाने की लागत को अलग तरीके से कैसे माना जा सकता है। पूंजी जुटाने में किए गए व्यय बिल्कुल उसी चरित्र के व्यय हैं जो कंपनी बनाते वक्त जुटाई गयी हो या उसके बाद जुटाई गई हो: टेक्सास लैंड एंड मॉर्टगेज कंपनी बनाम विलियम होल्थम (3 टी.सी. 255)"।

39 उन्होंने आगे कहा कि "जब तक कानून प्रारंभिक खर्चों और सद्भावना को संपत्ति के रूप में मानने की अनुमति देता है, यद्यपि अमूर्त प्रकृति की, तब तक खर्च किया गया पैसा उतनी ही पूंजीगत व्यय की प्रकृति में है, जितना कि भूमि और मशीनरी खरीद में खर्च किया गया पैसा।" मुख्य न्यायाधीश ने तदनुसार माना कि रु. 28 लाख को केवल

कंपनी के व्यवसाय का मुनाफ़ा कमाने के उद्देश्य से किया गया व्यय (पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं) नहीं माना जा सकता। शाह, जे. भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे, और उन्होंने सोचा कि टेक्सास लैंड एंड मॉर्टगेज कंपनी बनाम विलियम होल्थम (3 टी.सी. 255) में अनुपात निर्णय और रॉयल इंश्योरेंस कंपनी बनाम वाटसन ((1897) A.C.1) में निर्णय के अंतर्निहित सिद्धांत इस निष्कर्ष का समर्थन करता है।

40 इस स्तर पर टेक्सास लैंड एंड मॉर्गेज कंपनी बनाम विलियम होल्थम (3 टी.सी. 255) के मामले पर विचार करना सुविधाजनक होगा, जिस पर इस निर्णय में भरोसा किया गया था। हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि इंग्लैंड में क़ानून भारत के कानून से भिन्न है और अंग्रेजी आयकर अधिनियम की पृष्ठभूमि के प्रकाश में अंग्रेजी मामलों में विद्वान न्यायाधीशों की टिप्पणियों की सराहना की जानी चाहिए। इस मामले में एक बंधक कंपनी ने डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक जारी करके धन जुटाया था और बंधक जारी करने और ऐसे डिबेंचर और डिबेंचर-स्टॉक रखने के लिए खर्च किया था। कंपनी ने इन खर्चों में कटौती करने का दावा किया लेकिन उच्च न्यायालय ने माना कि खर्चों को अंग्रेजी आयकर अधिनियम की अनुसूची डी के तहत व्यापार खर्च के रूप में नहीं काटा जा सकता है।

मैथ्यू, जे. ने दावे को अस्वीकार करने के लिए निम्नलिखित कारण बताए:

41 "डिबेंचर पर पैसा जुटाने के लिए भुगतान की गई राशि, डिबेंचर पर दी गई अग्रिम राशि से आती है, और इसलिए, इसे प्राप्त करने की लागत के लिए इतना भुगतान किया जाता है, लेकिन ऐसी कम्पनी जिसके पास अपने सम्सत कार्यो के परिचालन के लिये पर्याप्त धन है एवं दुसरी जो मात्र सुविधा के भुगतान से संतुष्ट है के लिये एक कानून नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से कल के निर्णय से समाप्त हो गया है। (एंग्लो-कॉन्टिनेंटल गुआनो वर्क्स बनाम बेल(3 टी.सी. 239)।"

42 बहस के दौरान, केव जे., ने टिप्पणी की:

43 "यह केवल इतनी ही पूंजी है। एक आदमी £100,000 पूंजी जुटाना चाहता है, और ऐसा करने के लिए उसे £4,000 का भुगतान करना होगा। इससे पूंजी £96,000 हो जाती है: बस इतना ही।"

44 फिनले, क्यू.सी. के तर्क के उत्तर में, कि "कंपनी की पूंजी, जिसे उचित रूप से कहा जाता है, शेयर पूंजी है", केव, जे. ने टिप्पणी दी:

45 "जिस हद तक आप उधार लेते हैं आप कंपनी की पूंजी बढ़ाते हैं।"

46 हमारी राय में, यदि कोई अंग्रेजी आयकर अधिनियम की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखता है, तो ऊपर दी गई टिप्पणियों का भारतीय आयकर अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों से कोई प्रासंगिकता नहीं है। नियम 3 के सामने, केस 1, धारा 100 (5 और 6 वि. अध्याय 35) पूंजी के रूप में नियोजित या नियोजित की जाने वाली किसी भी राशि के संबंध में किसी भी व्यय की कटौती पर रोक लगाता है, मैथ्यू और केव, जेजे केवल इस सवाल से चिंतित थे कि क्या डिबेंचर द्वारा सुरक्षित की गई राशि और डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक जारी करने से प्राप्त राशि को इस नियम के अर्थ के भीतर नियोजित पूंजी कहा जा सकता है या नियोजित किया जाना चाहिए। सही या गलत, अंग्रेजी न्यायालयों ने माना है कि डिबेंचर जारी करने से प्राप्त राशि नियम के अर्थ में नियोजित पूंजी है, लेकिन हमें इस से 'पूंजीगत व्यय' शब्दों की व्याख्या करने में कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है जो अधिनियम की धारा 10(2)(xv) मे उल्लेखित है। हमारी राय में, बॉम्बे हाई कोर्ट का टेक्सास लैंड एंड मॉर्गेज कंपनी बनाम विलियम होल थाम (3 टी.सी. 255) पर भरोसा करना गलत था। लेकिन हम यह नहीं कहते कि टाटा आयरन एंड स्टील (1 आई.टी.सी. 125) मामले का फैसला गलत था। शेयरों को जारी करके पूंजी प्राप्त करना डिबेंचर द्वारा ऋण प्राप्त करने से भिन्न है।

47 नागपुर इलेक्ट्रिक एंड लाइट कंपनी बनाम आयकर आयुक्त(6 आई.टी.सी. 28) के मामले में, न्यायिक आयुक्त, नागपुर की अदालत ने

माना कि डी.सी. से ए.सी. में करंट की आपूर्ति की प्रणाली को बदलने और पूर्व मे लिये गये ऋण के उन्मोचन के लिए डिबेंचर ऋण जुटाने के लिए खर्च को मूल्यांकन योग्य आय में कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं था। न्यायिक आयुक्त ने टेक्सास लैंड एंड मॉर्टगेज कंपनी बनाम विलियम होल्थम (6 आई.टी.सी. 28) और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (1 आई.टी.सी. 125) के मामले का पालन किया। इन दो मामलों का उल्लेख करने के बाद, एकमात्र अतिरिक्त कारण यह दिया गया कि "प्राधिकार की दृष्टि के अलावा हमें यह उचित प्रतीत होता है कि पूंजी प्राप्त करने के लिये व्यय किया गया धन को पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाना चाहिए" । बड़े सम्मान के साथ हम यह मानते है कि यह मामला गलत रूप से निर्णित किया गया।

48 वेस्टर्न इंडिया प्लाइवुड लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास (38 .आई.टी.आर.533) में केरल उच्च न्यायालय ने माना कि डिबेंचर द्वारा ऋण जुटाने के लिए कंपनी द्वारा किया गया व्यय एक पूंजीगत व्यय था और इसलिए धारा 10(2)(xv) के तहत कटौती योग्य नहीं था। उच्च न्यायालय ने यूरोपीय निवेश ट्रस्ट कंपनी बनाम जैक्सन(18 टी.सी.1) और एस्कॉट गैस वॉटर हीटर बनाम डफ(24 टी.सी. 171) और कुछ अन्य मामलों पर भरोसा करते हुए पूंजी उधार लेने और केवल अस्थायी या दिन-प्रतिदिन के आवास या व्यापारिक सुविधाएं के बीच अंतर किया। । उच्च न्यायालय के अनुसार, पूंजी उधार लेने के खर्च को राजस्व व्यय के रूप में

नहीं माना जा सकता है। यह अंतर अंग्रेजी कानून में मान्य हो सकता है लेकिन हम यह समझने में असमर्थ हैं कि यह अंतर भारतीय आयकर अधिनियम के तहत कैसे मान्य है। चूंकि निर्णय मुख्य रूप से इस अंतर पर आधारित है और अन्य बातों के साथ-साथ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (1 आई.टी.सी. 125) और नागपुर इलेक्ट्रिक एंड लाइट कंपनी बनाम आयकर आयुक्त (6 आई.टी.सी. 28) पर निर्भर करता है, हमें सम्मानपूर्वक यह मानना चाहिए कि केस को गलत रूप से निर्णित किया गया।

49 विजागपट्टनम शुगर्स एंड रिफाइनरी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त(47 आई.टी.आर. 139) में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने टेक्सास लैंड एंड मॉर्टगेज कंपनी बनाम विलियम होल्थम (3 टी.सी. 255) और वेस्टर्न इंडिया प्लाइवुड लिमिटेड बनाम सीआईटी, मद्रास(38 .आई.टी.आर.533) के निर्णयो के प्रकाश मे पाया कि उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर,निधारीती कम्पनी द्रारा चीनी के प्रत्येक मन पर किया गये चार आने की दलाली और कमीशन के भुगतान को राजस्व व्यय नही माना बल्कि पूंजी व्यय माना हमारी राय में, जहां तक बोकरेज का सवाल है, यह निर्णय गलत था, लेकिन जहां तक माल की बिक्री पर कमीशन का सवाल है, इस मामले में हम इस फैसले के संबंध में कुछ नहीं कहते हैं।

50 कलकत्ता उच्च न्यायालय ने श्री अन्नपूर्णा कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (54 आई.टी.आर.592), बच्चावत, जे. ने मामले में प्रश्न की विस्तार से जांच की, जिसमें माना गया कि कम्पनी द्वारा प्राप्त रुपये 10 लाख का ऋण निर्धारिती के व्यवसाय के स्थायी लाभ के लिए एक संपत्ति या लाभ था। उन्होंने कई मामलों पर भरोसा जताया, जिनमें से कुछ पर हम पहले ही विचार कर चुके हैं। लेकिन हम इस बात पर सहमत होने में असमर्थ हैं कि प्राप्त ऋण को व्यवसाय के स्थायी लाभ के लिए एक संपत्ति या लाभ के रूप में माना जा सकता है ऋण एक दायित्व है और उसे चुकाना पड़ता है और, हमारी राय में, विस्काउंट केव द्वारा निर्धारित और कई मामलों में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित और लागू किए गए परीक्षण के भीतर एक दायित्व को एक परिसंपत्ति या लाभ के रूप में मानना गलत है। सिन्हा, जे.,. द्वारा कई मामलों का जिक्र करने के बाद, महसूस किया कि डिबेंचर जारी करके पूंजी जुटाना का एक मान्यता प्राप्त तरीका था और उन्होंने महसूस किया कि निर्णित किए गए मामलों मे यह निष्कर्ष रखा गया है कि डिबेंचर जारी करके धन उधार लेना एक पूंजीगत परिसंपत्ति का अधिग्रहण था- और उसके संबंध में किया गया कोई भी कमीशन या व्यय पूंजीगत प्रकृति का था और इसे राजस्व की प्रकृति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। वह इस बात से प्रभावित थे कि इसके विपरीत एक भी मामला उनके संज्ञान में नहीं लाया गया। लेकिन हमें मामले को सैद्धांतिक रूप से तय करना होगा, और सम्मान के साथ

हमें यह लगता है कि उन्होने अधिनियम की धारा 10(2)(xv) के तहत ऋण को पूंजी के बराबर मानने में गलती की है।

51 एस. एफ. इंजीनियर बनाम आयकर आयुक्त (57 आई.टी.आर.455) में, द बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि किसी व्यवसाय को चलाने के लिए , लिये गये ऋण को जुटाने पर किये गये खर्च को हर मामले मे पूंजीगत प्रकृति के व्यय के रूप में नही रखा जा सकता । मामले के तथ्यों पर उन्होंने माना कि इमारत का निर्माण और बिक्री फर्म का एक मात्र व्यवसाय था एवं बिल्डिंग व्यपार का कुल माल था और जो ऋण उठाया गया वह पूरी तरह से इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था ना की किसी अचल संपत्ति को प्राप्त करने के लिए या कोई प्रारंभिक पूंजी जुटाने के लिये अथवा निर्धारिती के व्यवसाय को बढाने के लिये उपयोग मे लिया था। ऋण प्राप्त करने के लिये जो व्यय हुआ वह पूंजीगत प्रकृति का व्यय नही था अपितु राजस्व व्यय था हालांकि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष सही था, परंतु हम इस सिद्धांत से सहमत नही हैं कि ऋण लेने के लिये व्यय की प्रकृति ऋण के प्रकृति और उद्देश्य पर निर्भर करेगा। जब बातचीत की जाती है तो ऋण लेने का उददेश्य कच्चे माल की खरीद हो सकता है, लेकिन कंपनी ऋण लेने के बाद अपना मन बदल सकती है और इसे पूंजीगत संपत्ति सुरक्षित करने पर खर्च कर सकती है। क्या जिस समय ऋण पर बातचीत की जा रही है उस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए या जिस उद्देश्य के लिए इसका वास्तव में उपयोग किया गया उस पर जा

रहा है? इसके अलावा मान लीजिए कि लेखांकन वर्ष में उद्देश्य उधार लेना और कच्चा माल खरीदना है, लेकिन मूल्यांकन वर्ष में कंपनी को कच्चा माल खरीदना अनावश्यक लगता है और इसे पूंजीगत संपत्ति पर खर्च करती है। क्या आयकर अधिकारी इस संदर्भ में मामले का निर्णय इस आधार पर करेगा कि लेखांकन वर्ष में क्या हुआ या इस आधार पर की मूल्यांकन वर्ष में क्या हुआ? हमारी राय में, नागपुर इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी बनाम आयकर आयुक्त (6 आई.टी.सी. 28) मामले में नागपुर न्यायिक आयुक्त द्वारा यह सही माना गया था कि जिस उद्देश्य के लिए नए ऋण की आवश्यकता थी, वह इस प्रश्न पर विचार करने के लिए अप्रासंगिक था की क्या ऋण प्राप्त करने का व्यय राजस्व व्यय था या पूंजीगत व्यय।

52 मामले के इस भाग को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, हमारी राय है कि (ए) प्राप्त ऋण स्थायी प्रकृति की संपत्ति या लाभ नहीं है; (बी) यह व्यय एक निश्चित अवधि के लिए धन के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था; और (सी) जिस उद्देश्य से ऋण प्राप्त किया गया था उस पर विचार करना अप्रासंगिक है। परिणामस्वरूप, मामले की परिस्थितियों में, व्यय धारा 10(2)(xv) के भीतर राजस्व व्यय था।

53 श्री देसाई का अंतिम तर्क यह है कि भले ही यह राजस्व व्यय हो, इसे पूरी तरह और विशेष रूप से व्यवसाय के उद्देश्य से नहीं रखा गया था। सुब्बा राव, जे., ने आयकर आयुक्त बनाम मलयालम

प्लांटेशन((1964)7 एस.सी..आर.693:53 आई.टी.आर.140) के मामले के कानून की समीक्षा की और इस प्रकार देखा:

> 54 "व्यापार के उद्देश्य के लिए" अभिव्यक्ति का दायरा "मुनाफा कमाने के उद्देश्य से" अभिव्यक्ति की तुलना में व्यापक है। इसका दायरा व्यापक है: इसमें न केवल व्यवसाय के दिन-प्रतिदिन के संचालन को शामिल किया जा सकता है, बल्कि इसे तर्कसंगत भी बनाया जा सकता है। इसके प्रशासन और इसकी मशीनरी के आधुनिकीकरण में; इसमें व्यवसाय के संरक्षण और इसकी परिसंपत्तियों और संपत्ति की ज़ब्ती, जबरदस्ती प्रक्रिया या शत्रुतापूर्ण स्वामित्व के दावे से सुरक्षा के उपाय शामिल हो सकते हैं; यह वैधानिक भुगतान को भी समझ सकता है किसी व्यवसाय को शुरू करने या चलाने के लिए पूर्व शर्त के रूप में लगाए गए बकाया और कर; इसमें व्यवसाय को चलाने के लिए कई अन्य प्रासंगिक कार्य शामिल हो सकते हैं।"

55 श्री देसाई का कहना है कि इस मामले में पैसे उधार लेने का कार्य किसी व्यवसाय को चलाने के लिए आकस्मिक नहीं था। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं. ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त (20 आई.टी.आर.1) मामले में इस न्यायालय ने माना कि

ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, एक निवेश कंपनी, जब उसने डिबेंचर पर पैसा उधार लिया था, तो उसके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज केवल भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 12(2) के तहत आय, लाभ या लाभ अर्जित करने के लिये किया गया। इसने तथ्यों की समीक्षा में पाया कि लेन-देन कंपनी के व्यवसाय को चलाने की सुविधा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से स्वेच्छा से किया गया था और वाणिज्यिक समीचीनता के आधार पर किया गया था। यह मामला, हमारी राय में, सीधे तौर पर वर्तमान मामले को कवर करता है, हालांकि श्री देसाई का सुझाव है कि एक निवेश कंपनी का मामला एक विनिर्माण कंपनी के मामले से अलग स्तर पर है। कुछ मामलों में, उनकी स्थिति भिन्न हो सकती है लेकिन इस प्रश्न का निर्धारण करने में कि क्या धन जुटाना किसी व्यवसाय के लिए आकस्मिक है या नहीं, हम एक निवेश कंपनी और एक विनिर्माण कंपनी के बीच कोई अंतर नहीं समझ सकते हैं। हम उल्लेख कर सकते हैं कि उस मामले में यह न्यायालय इस बात पर विचार नहीं कर रहा था कि व्यय पूंजीगत व्यय की प्रकृति में था या नहीं, क्योंकि इस बात पर सभी सहमत थे कि व्यय पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं था, और एकमात्र प्रश्न जो यह था न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या व्यय केवल आय, लाभ या प्राप्ति अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया था।

56 धर्मवीर धीर बनाम आयकर आयुक्त ((1961) 3 एस.सी..आर.359 : 42 .आई.टी.आर.7) का मामला भी उस निष्कर्ष का

समर्थन करता है जिस पर हम मामले के इस भाग पर पहुंचे हैं। उस मामले में यह माना गया था कि ऋणदाता से ऋण प्राप्त करने के लिए एक समझौते के अनुसरण में ब्याज का भुगतान और निर्धारिती के व्यवसाय के मुनाफे के 11/16 वें हिस्से के बराबर राशि का भुगतान पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यावसायिक अर्थों में किया गया व्यय था जो निर्धारिती के व्यवसाय के प्रयोजन के लिए किया गया था और इसलिए, वे कटौती योग्य राजस्व व्यय थे।

57 निष्कर्ष पर पहुचने से पहले हमें श्री शास्त्री द्वारा उठाए गए बिंदु का निस्तारण करना चाहिए कि क्या उच्च न्यायालय ने अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्षों की तुलना में आयकर अधिकारी के निष्कर्षों को प्राथमिकता देकर कानूनी गलती की है। इस प्रश्न का निर्णय करना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि एक निर्देश में उच्च न्यायालय को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किए गए तथ्य के निष्कर्षों को स्वीकार करना चाहिए और यह उस व्यक्ति के लिए है जिसने निर्देश के लिए आवेदन किया है कि वह पहले धारा 66(1) उन निष्कर्षों को चुनौती दे। यदि वह धारा 66(1) के तहत आवेदन दायर करके तथ्य के निष्कर्षों की वैधता के बारे में सवाल नही उठाता तो वह उच्च न्यायालय के समक्ष यह आग्रह करने का हकदार नहीं है कि निष्कर्ष किसी न किसी कारण से दूषित हैं।

`58 निष्कर्ष के तौर पर हम मानते हैं कि रुपये 84,633/- का व्यय पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं था और निर्धारिती के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित या व्यय किया गया था। इसलिए, संदर्भित प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए। अपील स्वीकार की जाती है, उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त किया जाता है और संदर्भित प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप मे दिया जाता है। अपीलकर्ता को यहां और उच्च न्यायालय में इसका खर्च वहन करना होगा।

अपील स्वीकार.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कौशल सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।